

गोडावण वाले राधेश्याम विश्नोई थे थार में जीवन का प्रहरी

राधेश्याम विश्नोई—जिनके व्यक्तित्व में सादगी, संकल्प और संवेदना की त्रिवेणी थी। वे न केवल जैसलमेर के गोडावण संरक्षण अभियान के नायक थे, बल्कि अपने व्यवहार, सोच और कार्यप्रणाली से एक प्रेरणास्रोत बन चुके थे। विश्नोई परंपरा की गोद में पले-बढ़े राधेश्याम ने अपनी युवा ऊर्जा को आधुनिक विज्ञान और परंपरागत लोक-ज्ञान के मेल से जोड़ा। उन्होंने यह कभी नहीं चाहा कि लोग उन्हें किसी नेता, पर्यावरणविद् या नायक के रूप में देखें—वे खुद को बस गांव का एक साधारण युवक भी मानते रहे। राधेश्याम जैसलमेर के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखते थे, पर उनका हृदय समूचे थार के लिए धड़कता था। वे विश्नोई समुदाय की उस परंपरा के जीवंत प्रतीक थे, जो सैकड़ों वर्षों से वन्यजीव और प्रकृति की रक्षा को धर्म मानती आई है। उन्होंने न केवल गोडावण को बचाने के लिए अपने जीवन की दिशा तय की, बल्कि रेगिस्तान में जैव विविधता के संरक्षण को लेकर एक सामाजिक आंदोलन की नींव भी रखी।

जैव विविधता के संरक्षण को लेकर एक सामाजिक आंदोलन की नींव भी रखी। 1926 में बड़बो पार्टी (Badbo) गोपनीय



जाता-तब भी वे निराश नहीं होते। उनका कहना था, 'गोडावण जैसे जीव को बचाना सिर्फ एक प्रजाति की रक्षा नहीं है, यह हमारी आत्मा को बचाने जैसा है।'

2025 में जब सेंचुरी एशिया पत्रिका ने उन्हें द

गोडावण मेन आफ इंडिया की उपाधि दी, तब वे मात्र 28 वर्ष के थे। लेकिन यह

सम्मान केवल उनके युवा प्रयासों की नहीं, बल्कि उनकी दूरदर्शिता, प्रतिबद्धता और आत्मीयता का प्रतीक था। उन्होंने कई बार कहा, 'अगर हम अपने पूर्वजों की तरह प्रकृति से रिश्ता बनाकर जिएं, तो पृथ्वी को बचाना कठिन नहीं है।'

दुर्भाग्यवश, इसी वर्ष 24 मई को एक सड़क दुर्घटना में राधेश्याम का असामिक निधन हो गया। यह न केवल जैसलमेर, बल्कि सपूचे भारत के लिए एक अपूरणीय क्षति थी। उनके निधन के बाद जैसलमेर में हजारों ग्रामीणों ने मौन जुलूस निकालकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आज भी वहां की बालू रेत में जब गोडावण की पदचिन्ह उभरते हैं, तो लोगों को राधेश्याम की याद आती है। राधेश्याम विश्नोई ने यह सिखाया कि किसी एक व्यक्ति की आस्था और कर्मठता पूरे पारिस्थितिक तंत्र को नया 'जीवन दे सकती है। वे चले गए हैं, लेकिन उनके 'गोडावण' आज भी उड़ रहे हैं—थार की उस खुली छाती पर, जिसे राधेश्याम ने जीवन भर बचाने की कोशिश की। लेकिन वे आज भी हर उस युवा के हृदय में जीवित हैं, जो प्रकृति के लिए कुछ करना चाहता है। उनकी स्मृति में जो काम आगे बढ़ रहे हैं—वे ही उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हैं।

सामयिक

सुरेश उपाध्याय



इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सबसे पहले और सबसे तेज 'एक्सवलूसिव' (सिफ आपके लिए) की होड लगी रहती है। इस उतावलेपन में सत्य व तथ्य की जांच भी जरुरी नहीं समझी जाती है और एक फुटनोट 'हमारा चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है' से जिम्मेदारी की झितशी कर ली जाती है। इसका एक ताजा उदाहरण 'ऑपरेशन सिंदूर' के समय की गई रिपोर्टिंग में भी देखा जा सकता है। कैसी असत्य व मनमानी रिपोर्टिंग की गई, कैसा युद्धोन्माद उत्पन्न किया गया और आज जब वैश्विक स्तर पर छिछलेदारी हो रही है तो कोई जवाबदेही को तैयार नहीं है। वैकल्पिक कहा जाने वाला सोशल मीडिया इस उतावलेपन का ध्वज वाहक बना हुआ है। कापी, पेस्ट, फॉरवर्ड की बाढ़ सी आ गई है। इसी क्रम में एक नवीनतम उदाहरण एक नवविवाहित जोड़े की शादी, हनीमून व हत्या से जूड़े प्रकरण का है।

दख्खा जा सकता हा कसा असत्य व मनमानी रिपोर्टिंग की गई, कैसा युद्धोन्माद उत्पन्न किया गया और आज जब वैधिक स्तर पर छिछलेदारी हो रही है तो कोई जवाबदेही को तैयार नहीं है। वैकल्पिक

उतावलेपन के रोग से मुक्ति जरूरी

कई तरह का नकारात्मक टिप्पणीय सामने आई और बांग्लादेश की मानव तस्करी तक की चर्चाएं हुईं। प्रतिदिन की रिपोर्टिंग के साथ धारणाएं बनाने वाले सक्रिय हो गए,



नियम दृढ़ जान रहा, नियम नियम जान लगे। आज एक के प्रति सद्भावना व सहानुभूति तो दूसरे दिन दूसरे के प्रति वही भाव। आज का हीरो/हीरोइन दूसरे दिन विलेन निकल जाता है। इस विषय के प्रति

बालश्रमः विकास की राह का अवरोधक

इस वर्ष 'विश्व बालश्रम निषेध दिवस' की थीम है 'प्रगति स्पष्ट है, लेकिन अभी और काम करना बाकी है: आइये प्रयासों में तेजी लायें' यह बात साफ़ तौर पर स्वीकार करती है कि कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन माँजिल अब भी दूर है। मध्यप्रदेश जैसे राज्य, जहां गरीबी, पलायन, और सामाजिक असमानता गहरे हैं, वहाँ यह चुनौती और भी कठिन हो जाती है। अगर हम मध्यप्रदेश की स्थिति पर नज़र डालें, तो 2011 की जनगणना में 5-14 वर्ष के आयु वर्ग में देशभर में 1.01 करोड़ बाल श्रमिक दर्ज किए गए थे। परंतु 2022 के एनसीआरबी आंकड़ों में मध्यप्रदेश से बालश्रम मामलों की केवल 3 रिपोर्ट सामने आईं – यह दर्शाता है कि निगरानी तंत्र या तो निषिक्रिय है या फिर बालश्रम अब भी 'छिपा हुआ श्रम' बना हुआ है। हालांकि PENCIL पोर्टल पर वर्ष 2016 से 2021 के बीच पार्श्वान्तरों से जटे लगभग 2,891 बच्चों को बालश्रम से मुक्त कर आनंदर्पण की दिशा में कार्य किया गया, लेकिन यह भी प्रतीक्षी वर्ती दर्शाता है।

बालश्रम से मुक्त कर पुनर्वास की दिशा में कार्य किया गया, लेकिन यह भी पूरी तस्वीर नहीं दर्शाता है।



यह भी पूरी तस्वीर नहीं दर्शाता है। कानूनी स्तर पर भी चिंताएँ कम नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगई ने बालश्रम कानून में संशोधन को 'एक मृगमरीचिका' बताया था। उनका तर्क था कि वर्तमान कानून बच्चों को पूरी तरह सुरक्षा नहीं देता। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पारिवारिक व्यवसाय में काम करने की अनुमति देना या खतरनाक कामों की सूची को सीमित कर देना दरअसल बच्चों को छद्म तरीके से श्रम में धकेलना है। वास्तव में जब एक बच्चा अपने पिता की दुकान में काम करता है तो कानून उसे बालश्रम नहीं पाता, क्वैक्स वही काम करें

मजबूरी बन जाती है। मनरेगा
जैसी योजनाओं की असफलता,
पलायन और कर्ज़ जैसी स्थितियाँ
बच्चों को श्रम में धकेल देती हैं
और जब ये बच्चे काम करते हैं
तो कई बार नशे का शिकार हो
जाते हैं। ऐसे में उन्हें नशे से
निकालना बड़ी चानौती बनकर

सामने आती है।
हालांकि सरकार द्वारा बालश्रम समाप्त करने के लिए कई योजनाएँ भी चलाई गई हैं। राष्ट्रीय बालश्रम परियोजना (NCLP) के तहत हजारों बच्चों को बचाया गया है, पुनर्वास केंद्र खोले गए हैं, लेकिन इनका विस्तार और प्रभाव क्षेत्र अब भी सीमित है। PENCIL पोर्टल के ज़रिए निगरानी, शिकायत और कार्रवाई की प्रक्रिया को नियन्त्रित किया

नाना, लाकून धरा काने काई
और बच्चा मजदूरी के रूप में करे
तो वह अपराध बन जाता है। यह कानूनी विरोधाभास ही
है जो बालश्रम को पूरी तरह खत्म करने में सबसे बड़ी
है।

सामाजिक-आर्थिक स्तर पर समस्या और भी गंभीर है। ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में जब वयस्कों को ऐसा करने की जिम्मेदारी नहीं दी जाती है, तो वे अपनी जीवनशैली को बदल देते हैं।

प्रांतिया का डिजिटलाइटर एक पर्याप्त गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्प्रॅणाली की पहुँच अभी भी काफी सीमित है। बालश्रम की समस्या केवल लड़कों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दोनों लिंगों के लिए समान है।

